

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 19-11-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 19 Nov, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 3 – Environment / Prelims	सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्लीयरेंस को खारिज करने का फैसला वापस लिया
Page 06 Syllabus : GS 2 : Governance / Prelims	डीपीडीपी नियमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग अनुभाग बनाया गया
Page 06 Syllabus : GS 3 : Environment & Sustainable Development / Prelims	100 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों ने क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में जगह बनाई
In News Syllabus : GS 3 : Science & Technology	ऑपरेशन थियेटर में राग एनेस्थीसिया के उपयोग को कम करते हैं
समाचार में In News Syllabus : Prelims	स्थानीय निकाय 16वें वित्त आयोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं?
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : Governance	वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 - फिनलैंड शीर्ष पर क्यों है और भारत 118वें स्थान पर है

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2-1 के बहुमत के फैसले में मई 2024 के अपने पहले के फैसले को याद कर दिया है, जिसमें कार्योत्तर (पूर्वव्यापी) पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को अवैध घोषित किया गया था । नया निर्णय "असाधारण परिस्थितियों" में पूर्वव्यापी ईसी की अनुमति देता है, यह तर्क देते हुए कि प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकने से अर्थव्यवस्था और विकास पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने इस कदम को पर्यावरण न्यायशास्त्र से पीछे हटने और "उल्लंघन करने वालों के लिए लाभ" कहा।

SC recalls verdict rejecting green clearances

The majority 2-1 verdict upholds pleas in public interest; CJI says it would have 'devastating' effect

Justice Bhuyan records a sharp dissent, says court is backtracking for the sake of violators

In May, the court said retrospective clearances to regularise constructions were clearly illegal

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

A three-judge Bench of the Supreme Court, in a majority judgment on Tuesday, recalled its May 16 verdict declaring the Centre's grant of *ex post facto* or retrospective environmental clearances (ECs) to building projects and constructions a "gross illegality" and an "anathema".

Chief Justice of India B.R. Gavai, who is retiring on November 23, said in his separate opinion that the May 16 judgment, if allowed to continue to operate, would have a "devastating effect" and "thousands of crores of Rupees would go to waste".

Justice K. Vinod Chandran backed his view, forming the majority on the Bench.

Justice Ujjal Bhuyan recorded a sharp dissent in

his 97-page opinion. He termed the review judgment an "innocent expression of opinion" which overlooked the "very fundamentals of environmental jurisprudence".

The separate individual opinions of the Chief Justice and Justice Bhuyan clashed, with the latter saying he was pained to see the country's highest court "backtracking on sound environmental jurisprudence" for the sake of violators, even as the "deadly Delhi smog reminds us everyday about the hazards of pollution".

Justice Bhuyan was a member of the two-judge Bench, headed by the now-retired Justice A.S. Oka, which had delivered the May 16 judgment.

'Crafty drafting'
The May judgment had held that granting retrospective clearances in any

form to regularise illegal constructions was clearly illegal. The court had struck down a 2017 notification and 2021 office memorandum (OM) of the Union government, which in effect recognised the grant of *ex post facto* ECs.

It had found the Centre guilty of "crafty drafting" to clear illegal constructions through retrospective ECs.

The two-judge Bench had concluded that the government was only protecting the illegal actions of project proponents who started building or operations in these illegal constructions without obtaining the prior EC mandated by environmental protection laws.

The Chief Justice reasoned that striking down retrospective ECs would lead to the demolition of multi-crore private and public projects either in use

Divergent views

The Supreme Court's majority verdict and dissenting voice focus on different aspects of retrospective environmental clearances

CJI B.R. Gavai, Justice K. Vinod Chandran uphold review petitions: Continuation of the May 16 verdict striking down *ex post facto* ECs, will have a "devastating" impact on economy and development

Justice Ujjal Bhuyan finds no case for review: *Ex post facto* EC is anathema to the environment. Upholding the review would seem like the SC backtracking when a deadly smog is choking Delhi. A false narrative is being created, pitting the environment against development

Projects likely to be affected:

- 24 Central projects worth ₹8,293 crore
- 29 State-level projects worth ₹11,168 crore
- Loss to public exchequer to the tune of nearly ₹20,000 crore



or under construction, employing hundreds.

Chief Justice Gavai questioned the need for demolition of these structures when they could continue by paying heavy penalties. Many projects, including an investment by the Steel Authority of India (SAIL), a

have held that *ex post facto* ECs cannot be declined with "pedantic rigidity".

Ex post facto approval should not be withheld only as a penal measure, he said, adding that projects can be cleared retrospectively in exceptional circumstances and not as a routine. The top judge asked himself the question of whether it would be in public interest to demolish all these projects and throw the money spent on them into the dustbin.

"The question, therefore, is whether such a modus operandi of demolition and re-construction would be in the larger public interest or would in fact be counter-productive to the public interest?" the CJI asked.

Justice Bhuyan dismissed the CJI's "dustbin" query, saying it was founded on erroneous logic. He said the "question" should be

why the review judgment is so keen to "virtually prod" the Centre to grant *ex post facto* ECs to violators of the law.

'False narrative'
"It is unfortunate that a false narrative is being created pitting the environment against development... Environment law cannot countenance the notion of an *ex post facto* clearance. This is contrary to both the precautionary principle as well as the need for sustainable development," Justice Bhuyan observed.

Ecology and development are not adversaries, he stressed, adding that both were part of the Constitutional construct of sustainable development. Retrospective ECs, however, are an anathema – "a thing devoted to evil" – thrust on the environment, said Justice Bhuyan.

स्थैतिक संदर्भ

(A) पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) क्या है?

- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत एक सांविधिक अनुमोदन।
- प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण/संचालन से पहले आवश्यक ।
- सुनिश्चित:
 - पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
 - शमन के उपाय
 - सार्वजनिक परामर्श

(B) एक्स-पोस्ट फैक्टो क्लीयरेंस क्या है?

किसी परियोजना के निर्माण या संचालन के पहले ही शुरू होने के बाद दी गई स्वीकृति । परंपरागत रूप से इसके खिलाफ माना जाता है:

- एहतियाती सिद्धांत
- कानून का पर्यावरण शासन

वर्तमान संदर्भ

मई 2024 का फैसला (दो न्यायाधीशों की पीठ: न्यायमूर्ति एस ओका)

माना कि:

- ईसी के बिना निर्माण शुरू करना एक घोर अवैधता है
- पूर्वव्यापी चुनाव आयुक्त स्पष्ट रूप से अवैध हैं
- 2017 और 2021 की पूर्वव्यापी ईसी को सक्षम करने वाली सरकारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया गया था

नया नवंबर 2024 फैसला (तीन न्यायाधीशों की पीठ)

बहुमत: सीजेआई बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन

- मई 2024 के फैसले को याद किया
- असाधारण स्थितियों के लिए पूर्वव्यापी ईसी की अनुमति दी गई
- कहा कि प्रमुख केंद्र और राज्य परियोजनाओं को रोकने से जनहित को नुकसान होगा
- लगभग 24 केंद्रीय परियोजनाएं (₹8,293 करोड़) और 29 राज्य परियोजनाएं (₹11,168 करोड़) दांव पर थीं

जस्टिस भुइयां की असहमति

- पूर्वव्यापी चुनाव आव्रजन का कड़ा विरोध किया
- चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट "पीछे हट रहा है" और पर्यावरण न्यायशास्त्र को कमजोर कर रहा है
- कहा कि पर्यावरण और विकास को विरोधी ताकतों के रूप में गलत तरीके से चित्रित किया जा रहा है
- पूर्वव्यापी ईसी को "अभिशाप" कहा जाता है

(A) पर्यावरण बनाम विकास बहस

- बहुमत: विकास परियोजनाओं को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता
- असहमति: दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान अल्पकालिक आर्थिक लाभ से अधिक है

(B) एहतियाती सिद्धांत

- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का मूल
- पूर्वव्यापी चुनाव आयोग इस सिद्धांत का खंडन करता है

(C) प्रदूषक भुगतान सिद्धांत

- पूर्वव्यापी ईसी उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देकर अवैध निर्माण को नियमित करने की अनुमति दे सकते हैं
- प्रतिरोध को कमजोर करता है

(D) ईआईए प्रक्रिया की अखंडता

- पूर्व-प्रभाव अनुमोदन सक्षम करता है:
 - पर्यावरणीय उचित प्रक्रिया को दरकिनार करना

- अवैधताओं को वैध बनाना
- सामुदायिक भागीदारी को कमजोर करना

(E) सतत विकास

- दोनों पक्ष सतत विकास पर सहमत
- लेकिन इस पर मत:
 - "विकास पहले" बनाम
 - "पर्यावरण-केंद्रित अनुपालन"

महत्वपूर्ण तथ्य

1. पर्यावरण मंजूरी: ईआईए अधिसूचना, 2006
2. कार्योत्तर निर्वाचन आयोग: मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे अवैध ठहराया गया था
3. संवैधानिक रूप से प्रासंगिक सिद्धांत:
 - एहतियाती सिद्धांत
 - प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
 - सतत विकास
4. शामिल अधिकारी:
 - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 - राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए)
5. 2017 और 2021 सरकारी अधिसूचनाएं: सक्षम पूर्वव्यापी ईसी

संभावित MCQs

1. पूर्व-प्रभाव ईसी किससे संबंधित है?
→ ईआईए अधिसूचना 2006
2. "एहतियाती सिद्धांत" किससे जुड़ा है?
→ पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता
3. पूर्वव्यापी चुनाव आयुक्त को पहले अवैध घोषित किया गया था?
→ मई 2024 सुप्रीम कोर्ट का फैसला

समाप्ति

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पहले के फैसले को वापस लेना भारत के पर्यावरण न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जबकि बहुमत आर्थिक विकास और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देता है, असहमति कानून के पर्यावरणीय शासन के क्षरण को उजागर करती है। बहस एक नियामक ढांचे की आवश्यकता को दर्शाती है जो सतत और समावेशी विकास की सुविधा प्रदान करते हुए सख्त पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: पूर्व-प्रभाव पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह निर्माण या परियोजना संचालन शुरू होने से पहले प्रदान किया जाता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय (मई 2024) ने माना कि कार्योत्तर ईसी अवैध हैं और एहतियाती सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शासित होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: "भारत में पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी पर बहस पर्यावरण न्यायशास्त्र और विकास की अनिवार्यता के बीच एक गहरे संघर्ष को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के आलोक में चर्चा करें। (150 शब्द)"

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सहमति तंत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग श्रेणी बनाकर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 के मसौदे को संशोधित किया है। यह बदलाव इस बात की चिंता जताए जाने के बाद आया है कि विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को पहले बच्चों के साथ जोड़ा जाता था, जिसके लिए अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती थी, जिसे कार्यकर्ताओं ने समस्याग्रस्त और भेदभावपूर्ण करार दिया था।

जबकि विकलांगता समूहों ने अलगाव का स्वागत किया, उन्होंने अस्पष्ट संरक्षकता कानूनों, कार्यान्वयन चित्रों की कमी और डीपीडीपी अधिनियम के साथ भाषा विसंगतियों जैसे मुद्दों को चिह्नित किया।

Separate Section for disabled persons made in DPDP Rules

In the draft rule regarding consent mechanism, persons with disabilities had been clubbed with children; activists hail change but raise concern over lack of clarity on laws of guardianship

Aroon Deep
Abhinay Lakshman
NEW DELHI

Following pushback from disability rights activists, the Electronics and Information Technology Ministry has made changes to the Digital Personal Data Protection Rules, 2025, to separate persons with disabilities from a rule that, in a draft, clubbed them with children over consent from a guardian.

While activists hailed this change, they said concerns over the provisions remain. The notified rules do not contain illustrations on implementation to cover a range of instances where disabled persons may or may not be able to use the Internet freely. Further, the language of the DPDP Act, 2023, continues to group children and persons with disabilities together.

The DPDP Act, 2023, and the rules significantly restrict what minors can do online, such as setting up a social media account, without a parent's consent. In the draft rules, this requirement was spelled out in a section that included persons with disabilities, caus-

Step by step

Some helpful reforms have come through in the Digital Personal Data Protection Rules, 2025, to benefit persons with disabilities

REVISED TERMS

- Separation from children in consent rules termed a major win for disability rights
- The restrictions relating to behavioural monitoring, tracking, targeted advertising that apply to children do not apply to persons with disabilities anymore



REMAINING CONCERNS

- No illustrations for implementation scenarios
- Language in DPDP Act still groups children & persons with disabilities
- Guardianship laws unclear (NT Act vs RPWD Act)

ing concern among disability rights groups.

Nipun Malhotra, of the Nipman Foundation, which has been advocating for changes to the Act and rules, said it was a "major victory" to have the Sections governing consent mechanisms for children and persons with disabilities separated. "The restrictions relating to behavioural monitoring, tracking, targeted advertising that apply to children do not apply to persons with disabilities any more. These are useful features for persons with disabilities," he said. However, he

noted that concerns remain regarding the practicalities of implementing the rules and the language in the principal Act, where children and persons with disabilities are included in the same Section.

The part of the rules that deals with consent for children's data includes multiple illustrations of different scenarios under which consent should be obtained, along with a Schedule that exempts and clarifies these requirements. While the separation of the Sections has clarified that these restrictions will not be applicable to persons

with disabilities, the Section for persons with disabilities does not have any illustrations to capture the nuances of how guardianship operates, a key issue with the draft rules as pointed out in a report by the policy think tank PAC-TA and the NGO Saksham Disability.

Another issue pointed out by activists and civil society organizations was that the draft rules did not clarify which law of guardianship for persons with disabilities – either the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, and Multiple Disabilities Act, 1999, or the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 – would be considered for implementation.

The Saksham report raised concerns about this, given that under the NT Act, the need for guardianship is partly determined by a person's "decision-making capacity", a term that the 1999 law does not clearly define. This, activists say, is not in consonance with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, while guardianship under the RPWD Act aligns with it.

स्थैतिक संदर्भ

(A) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है
- मुख्य सिद्धांत: सहमति, उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनीकरण
- बच्चों और कमजोर व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए विशेष सुरक्षा

(B) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम)

- विकलांगता की 21 श्रेणियों को परिभाषित करता है
- समानता, गरिमा और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करता है
- सहायक निर्णय लेने के आधार पर "सीमित संरक्षकता" का परिचय देता है

(C) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

- व्यक्तियों के लिए लागू
 - स्वलीनता
 - प्रमस्तिष्काघात
 - मानसिक मंदता
 - एकाधिक विकलांगता
- कानूनी संरक्षकता से संबंधित है

(D) निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCPRD)

- भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है
- स्वायत्तता, सहमति, स्वतंत्रता पर जोर देता है

वर्तमान संदर्भ

पहले का अंक

- डीपीडीपी नियमों के मसौदे में दिव्यांगजनों को बच्चों के समान माना जाता है → माता-पिता/अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है
- भेदभावपूर्ण और स्वतंत्रता और स्वायत्तता के सिद्धांतों के खिलाफ देखा जाता है

नए संशोधित नियम

1. दिव्यांगजनों के लिए अलग अनुभाग
2. व्यवहार ट्रेकिंग पर प्रतिबंध, लक्षित विज्ञापन स्वचालित रूप से PwD पर लागू नहीं होंगे (ये केवल बच्चों पर लागू होते हैं)
3. स्पष्टीकरण कि दिव्यांगजन अपनी क्षमता के आधार पर स्वतंत्र रूप से सहमति दे सकते हैं

4. शेष चिंताएँ

(ए) कोई चित्र या व्यावहारिक परिदृश्य नहीं

नियमों में स्पष्टता का अभाव है:

- जब एक पीडब्ल्यूडी स्वतंत्र रूप से सहमति दे सकता है
- जब अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है
- ऑनलाइन सेवाओं को सहमति कैसे सत्यापित करनी चाहिए

(B) भाषा असंगति

डीपीडीपी अधिनियम अभी भी क्लब करता है:

- पीडब्ल्यूडी
- बच्चेकुछ वर्गों में, जो नए नियमों का खंडन करता है।

(C) संरक्षकता अस्पष्ट बनी हुई है

- NT अधिनियम (1999) "निर्णय लेने की क्षमता" का उपयोग करता है
- RPwD अधिनियम (2016) "सीमित संरक्षकता" का उपयोग करता है
- डीपीडीपी नियम यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि कौन सा कानून लागू होता है
- यूएनसीआरपीडी पूर्ण संरक्षकता को हतोत्साहित करता है

(D) दिव्यांगजनों के मामले में सहमति प्रबंधकों के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं

विशेष रूप से इसके लिए:

- ऑनलाइन बैंकिंग
- सोशल मीडिया
- सरकारी डिजिटल सेवाएं

(1) स्वायत्तता बनाम संरक्षण

- ओवररेग्यूलेशन स्वायत्तता का उल्लंघन करता है
- अंडर-रेग्यूलेशन जोखिम शोषण

(2) कानूनों में सामंजस्य का अभाव

के बीच संघर्ष:

- डीपीडीपी अधिनियम
- RPwD अधिनियम
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियमपरिचालन भ्रम पैदा करता है।

(3) डिजिटल सेवाओं की पहुंच

पीडब्ल्यूडी को अक्सर सामना करना पड़ता है:

- खराब इंटरफ़ेस डिज़ाइन

- अस्पष्ट सहमति प्रपत्र
- सुलभ मोड का अभाव (ऑडियो, ब्रेल, सरल पाठ)

(4) कार्यान्वयन चुनौतियाँ

- पीडब्ल्यूडी की क्षमता कौन निर्धारित करता है?
- प्लेटफॉर्म संरक्षकता की पुष्टि कैसे करेंगे?
- अभिभावक शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ क्या सुरक्षा मौजूद है?

संभावित एमसीक्यू पर पूछा जा सकता है:

- डीपीडीपी अधिनियम, 2023 का उद्देश्य और दायरा
- बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की परिभाषा और अधिकार
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 → संरक्षकता
- यूएनसीआरपीडी सिद्धांत (स्वायत्तता, गैर-भेदभाव, समावेशन)

समाप्ति

डीपीडीपी नियमों में दिव्यांगजनों के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण अधिक स्वायत्तता और डिजिटल समावेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालाँकि, व्याख्या, संरक्षकता स्पष्टता और कार्यान्वयन तंत्र के संबंध में पर्याप्त चुनौतियाँ बनी हुई हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए, भारत को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप एक सामंजस्यपूर्ण कानूनी ढांचे, स्पष्ट प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश और समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संशोधित मसौदा नियमों में, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को अब सहमति प्राप्त करने के लिए बच्चों के साथ नहीं जोड़ा गया है।
2. डीपीडीपी अधिनियम, 2023 बच्चों और विकलांग व्यक्तियों दोनों के लिए व्यवहार ट्रेकिंग पर समान प्रतिबंध लगाता है।
3. इन नियमों को डीपीडीपी अधिनियम, 2023 से कानूनी समर्थन प्राप्त होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : "डीपीडीपी नियमों में विकलांग व्यक्तियों को बच्चों से अलग करना एक स्वागत योग्य सुधार है, लेकिन संरक्षकता पर स्पष्टता का अभाव प्रमुख कार्यान्वयन चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। चर्चा करना। (250 शब्द)

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी 2026 काकेरेली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा जारी की गई थी, जिसमें दिखाया गया है कि सूची में 103 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं - जो अमेरिका, चीन और यूके के बाद विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा है। रैंकिंग संस्थानों का उनके पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता प्रदर्शन पर आकलन करती है, जलवायु कार्रवाई, नैतिक शासन, रोजगार क्षमता और सामाजिक प्रभाव पर वैश्विक फोकस को दर्शाता है। शीर्ष भारतीय प्रदर्शनकर्ताओं में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं, हालांकि कई भारतीय संस्थानों में उनके संकेतक-स्तर के रैंक में गिरावट देखी गई है।

Over 100 Indian universities make it to QS sustainability rankings

Abhinay Lakshman
NEW DELHI

The London-based QS Quacquarelli Symonds on Tuesday released its QS World University Rankings for Sustainability 2026, showing that India, with 103 universities, had the fourth-highest number of institutions in the list, behind the United States, China, and the United Kingdom.

The QS sustainability rankings, established in 2023, assess institutions across environmental and social sustainability categories such as environmental impact, social impact, and governance. These include indicators covering environmental research, sustainability, and education, along with equality, employability, knowledge exchange, and health and wellbeing.

Report card

India, with 103 universities, has the fourth-highest number of institutions on the list, behind the U.S., China, and the U.K.

■ **Total Institutions Ranked:**
~2,000 from 100+ locations

■ **Top university globally:**
Lund University (Sweden)

TOP PERFORMERS IN INDIA

■ **IIT Delhi:** 93rd in Employability & Outcomes

■ **IIT Kharagpur:**
96th in Employability & Outcomes

■ **Delhi University:**
94th in Knowledge Exchange

The rankings released on Tuesday showed institutions from the U.K., Canada, Sweden, and the U.S. dominating the top 15, with Lund University in Sweden taking the top position. This year's edition features close to 2,000 institutions from over 100 locations worldwide.

Of the 103 Indian universities featured, the Indian Institute of Technology,

Delhi was the best performing, placed at 205. Overall, QS noted that India had 12 universities in the top 500, matching the number for countries such as China and the Netherlands.

While this is IIT, Delhi's highest position in the sustainability rankings since their inception, it is lower in relative terms compared to its performance last year, when around 1,700

institutions were ranked. Among the top 15 Indian universities in this year's sustainability rankings, nine saw their positions drop from the previous year's. These included Jadavpur University, IIT, Kanpur, IIT, Madras, the Indian Institute of Science, and others.

Across the 103 Indian institutions ranked, 30 saw their positions decline, 32 improved, and 15 remained unchanged. At the indicator level, IIT, Delhi (93rd) and IIT, Kharagpur (96th) made it to the top 100 globally for Employability and Outcomes. The University of Delhi entered the top 100 for Knowledge Exchange, at 94.

In a statement, Jessica Turner, CEO of QS, said "Overall, Indian universities excel in knowledge exchange and environmental sustainability."

स्थैतिक संदर्भ

एक। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग क्या है?

2023 में शुरू की गई, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग विभिन्न विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है:

VISHV UMIYA FOUNDATION INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES (VUFICS)

C/O. RADIANT SCHOOL OF SCIENCE , KH - 0, STHAPAN - 2 FLAT, KH ROAD, GANDHINAGAR - 382421, GUJARAT.

1. पर्यावरणीय प्रभाव

- स्थिरता अनुसंधान
- पर्यावरण शिक्षा
- जलवायु कार्रवाई
- संसाधन दक्षता

2. सामाजिक प्रभाव

- रोजगार और परिणाम
- ज्ञान का आदान-प्रदान
- सामाजिक न्याय
- स्वास्थ्य और कल्याण

3. शासन संकेतक

- नैतिक नीतियां
- संस्थागत पारदर्शिता

जन्म। यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- अंतर्राष्ट्रीयकरण के एनईपी 2020 लक्ष्यों का समर्थन करता है
- भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देगा
- परिसरों में स्थिरता-उन्मुख सुधारों को प्रोत्साहित किया

C. संबंधित स्थैतिक विषय

- एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई)
- वैश्विक शिक्षा रैंकिंग में भारत की प्रगति
- उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का शासन और स्वायत्तता
- परिसरों में पर्यावरणीय स्थिरता

वर्तमान संदर्भ**A. भारत का समग्र प्रदर्शन**

- 103 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग
- संस्थानों की संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है
- शीर्ष 500 में 12 भारतीय संस्थान

B. शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय संस्थान

- आईआईटी दिल्ली रोजगार और परिणामों के मामले में 93वें →
- आईआईटी खड़गपुर रोजगार और परिणामों में 96वें →
- दिल्ली विश्वविद्यालय → नॉलेज एक्सचेंज में 94वां

C. वैश्विक रुझान

- शीर्ष विश्वविद्यालय: लुंड विश्वविद्यालय (स्वीडन)
- यूके, कनाडा, स्वीडन, यू.एस.

D. भारत के लिए मिश्रित परिणाम

- 103 भारतीय संस्थानों में:
 - 30 रैंक में गिरावट आई
 - 32 बेहतर
 - 15 अपरिवर्तित

E. शीर्ष 15 भारतीय कलाकारों में गिरावट

शामिल:

- आईआईएससी
- आईआईटी मद्रास
- आईआईटी कानपुर
- आईआईटी खड़गपुर
- जादवपुर विश्वविद्यालय

मुद्दे + विश्लेषण**(A) ताकत**

1. बड़ी भागीदारी से पता चलता है कि भारत की वैश्विक शैक्षणिक उपस्थिति में सुधार हुआ है
2. स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखण को दर्शाता है
3. अनुसंधान आउटपुट और ज्ञान के आदान-प्रदान पर बढ़ते जोर का संकेत
4. भारतीय डिग्री के बारे में वैश्विक धारणा को बढ़ावा देता है

(B) चिंताएँ

1. गुणवत्ता बनाम मात्रा
 - 103 संस्थानों को रैंक करने के बावजूद, केवल कुछ ही शीर्ष वैश्विक स्तरों तक पहुंचते हैं
2. प्रदर्शन में गिरावट
 - 30 संस्थानों को गिराया गया, ठहराव दिख रहा है
3. पर्यावरणीय प्रभाव संकेतकों में कम अंक
 - भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में जलवायु अनुसंधान की तीव्रता में अभी भी पिछड़ रहे हैं
4. वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे में अंतर
 - अनुसंधान निधि सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% (कम) बनी हुई है
 -

5. सीमित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- वैश्विक धारणा और स्थिरता परिणामों को प्रभावित करता है

(C) आगे की राह

- अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश
- सतत परिसर (सौर, अपशिष्ट mgmt., जल संरक्षण)
- वैश्विक सहयोग में सुधार
- रोजगार + उद्योग संबंधों पर ध्यान दें
- शासन और पारदर्शिता को मजबूत करना

समाप्ति

क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 100 से अधिक संस्थानों के साथ भारत की मजबूत उपस्थिति उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

हालांकि, रैंक और स्थिरता स्कोर में सुधार के लिए गहरे संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होती है - बेहतर फंडिंग, मजबूत अनुसंधान संस्कृति, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और वैश्विक सहयोग। रणनीतिक फोकस के साथ, भारत मात्रा-संचालित भागीदारी से स्थिरता-केंद्रित उच्च शिक्षा में गुणवत्ता-संचालित वैश्विक नेतृत्व में परिवर्तन कर सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में उपयोग किए गए निम्नलिखित संकेतकों पर विचार करें:

1. रोजगार और परिणाम
2. ज्ञान का आदान-प्रदान
3. जलवायु कार्रवाई
4. संस्थागत पारदर्शिता

उपरोक्त में से कितने क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में शामिल हैं?

A. केवल दो B. केवल तीन C. केवल चार D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: "क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारत की बड़ी उपस्थिति प्रगति को दर्शाती है, लेकिन शीर्ष संस्थानों के बीच गुणवत्ता में गिरावट संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करती है। चर्चा करना। (150 शब्द)

In News : GS 3 : Science & Technology

आधुनिक चिकित्सा तेजी से दवा निर्भरता को कम करने और रोगी के परिणामों में सुधार करने के लिए गैर-औषधीय हस्तक्षेपों की पड़ताल करती है । लोक नायक अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हाल ही में दिल्ली स्थित एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण में पाया गया कि सर्जरी के दौरान हिंदुस्तानी रागों (यमन और किरवाणी) को सुनने से एनेस्थीसिया की आवश्यकता 15% कम हो जाती है, कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है और महत्वपूर्ण संकेत स्थिर हो जाते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवहार चिकित्सा का एक मजबूत संगम प्रदान करता है।

In Delhi study, ragas in the operation theatre cut anaesthesia use

Even under anaesthesia, the brain doesn't shut down; the auditory cortex still registers sound; as surgery begins, the body's stress systems stir and the levels of cortisol and other hormones rise, pushing up blood pressure to cope with the strain; the person feels nothing but the body still braces; music seems to mellow this response

Anupama Chandrasekaran

At first glance, the photograph looks like a scene from a science-fiction film or one of those viral, digitally altered images. A woman lies calm on an operating table under bright white lights, a headset snug over her ears. But it's real and was taken inside a hospital in New Delhi more than a year ago.

It's a snapshot of an unusual clinical trial by a group of anaesthesiologists from Lok Nayak Hospital and Maulana Azad Medical College. They wanted to investigate if music flowing through headsets during a minor surgery could soften the blow of strong medicines.

"All our surgeries are in completely new environments for patients and we give them general anaesthesia to produce unconsciousness," Sonia Wadhavan, director professor of Anaesthesia and Intensive Care at Maulana Azad Medical College, said. "But since all these groups of drugs come with some amount of side effects, we asked: if we integrate music therapy with our anaesthetic agents, can it help us reduce the requirement of these drugs?"

Dr. Wadhavan and her team designed a randomised controlled trial, which is a kind of experiment where people are split into groups by chance, like drawing names from a hat, to see if something truly works. One group listened to slow, soothing ragas for the entire surgery; the other did not. The results were telling: people who heard the music needed 15% less anaesthetic. Their heart rates stayed steady, their blood pressure held firm, and stress hormone levels fell. The study suggested that music helps patients heal with less strain and less medicine.

Soundtrack under the scalpel

The study, published in the October 2025 edition of the journal *Music and Medicine*, ran over 11 months. Fifty-six adults planning gallbladder removal, a common surgery to take out the small organ that holds digestive fluid used to break down fats, volunteered for this research.

The patients were split into two groups: one listened to soft flute and piano music during surgery; the other wore identical noise-cancellation headphones and were in silence.

The music the researchers chose wasn't random. It featured two Hindustani ragas: the bright, uplifting tones of Raga Yaman and the calm, soothing notes of Raga Kirvani. They chose these ragas because they believed the tones could gently steer the body's "fight or flight" system, which raises heart rate and blood pressure under stress, towards a calmer and steadier state.

"Since the ability to hear remains intact even under anaesthesia, we used



Every drop of drug and every minute saved can ease costs, speed recovery, and free beds. DR. FARAH HUSAIN/SPECIAL ARRANGEMENT

music therapy to study its effect on the sympathetic system and stress modulators like cortisol," Dr. Wadhavan said.

And it worked. Patients who listened to the music needed, on average, about 15% less propofol, a fast-acting anaesthetic that puts you under in seconds and keeps you pain-free and perfectly still. Not only that: their levels of cortisol, a hormone the body releases when it's stressed, were lower. The participants also needed fewer painkillers and had steady blood pressure throughout the surgery.

"It was a eureka moment," said Tanvi Goel, principal investigator and anaesthesiologist at Lok Nayak Hospital and Maulana Azad Medical College. "The music group not only required less anaesthesia but their stress levels were significantly lower."

Even under anaesthesia, the brain doesn't shut down. The auditory cortex still registers sound, catching rhythm and tone. As surgery begins – with its pokes, pricks, and cuts – the body's stress systems stir. The levels of cortisol and other hormones rise, pushing up blood pressure and blood sugar to cope with the strain. The person feels nothing but the body still braces. Music seems to mellow this response, releasing endorphins and oxytocin to steady the heart, ease stress, and support healing.



Since all these anaesthetics come with side effects, we asked: could music reduce the dosage required?

SONIA WADHAVAN
PROFESSOR OF ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE
AT MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE

"It's non-pharmacological, low-cost, and safe," said Farah Hussain, co-investigator and a certified music therapist. "All it needs is a Bluetooth device and a pair of headphones. There's no side-effect, only potential benefits."

'Complementary approaches'

Alex Street is a senior research fellow at the Cambridge Institute for Music Therapy Research in the UK. He studies how music stirs the brain, the nervous system, and emotions, and how it can be used in real therapy.

"What needs to happen is medicine always has to have a non-medical adjunct," Dr. Street said.

"Complementary approaches like music can reduce the need for medications that often have nasty side effects."

For instance, fentanyl is a synthetic

opioid often used to control severe pain during surgery. But just 2 mg of fentanyl can kill an adult human. It has become the leading cause of death for Americans aged 18 to 45, surpassing car accidents and gun violence. This is part of the opioid crisis, driven by the overuse of powerful painkillers. The epidemic shows why gentler ways to ease pain and stress are needed now more than ever.

In the Lok Nayak Hospital study, patients who listened to soothing music needed less fentanyl during surgery, signalling that non-drug approaches could reduce reliance on powerful painkillers.

Dr. Street added a practical reminder: that patients still need to hear the surgical team, even when the music plays.

"You can't just block everything out with noise-cancelling headphones," he said. "The patient needs to be able to hear what people are saying."

The Delhi team now hopes to test their music experiment with more surgeries and larger groups. In a country where hospitals overflow and resources are stretched thin, every drop of drug and every minute saved can ease costs, speed recovery, and free beds.

That image of a patient on an operating table with headsets on may soon feel less like science fiction and more like standard care.

anupama.c@thehindu.co.in

THE GIST

People who heard the music needed about 15% less anaesthetic, their heart rates stayed steady, their blood pressure held firm, and stress hormone levels fell; this suggested that music helps patients heal with less strain and less medicine

According to the researchers involved, music therapy is non-pharmacological, low-cost, and safe; all it needs is a Bluetooth device and a pair of headphones; there are no side effects, only potential benefits

Patients who listened to soothing music also needed less fentanyl, a potent opioid, during the surgery, signalling that non-drug approaches could help reduce reliance on powerful painkillers

करेंट अफेयर्स हाइलाइट्स

1. सर्जरी के दौरान प्रोपोफोल की आवश्यकता में 15% की कमी।
2. कम तनाव हार्मोन (कोर्टिसोल) और स्थिर हृदय गति और रक्तचाप।
3. ओपिओइड दर्द निवारक फेंटेनाइल की कम आवश्यकता, जो वैश्विक ओपिओइड संकट के बीच महत्वपूर्ण है।
4. राग यमन और राग किरवानी का उपयोग - उनके शांत शारीरिक प्रभावों के लिए चुना गया।

5. परीक्षण संगीत और चिकित्सा में प्रकाशित (अक्टूबर 2025)।
6. संसाधन की कमी वाले भारतीय अस्पतालों में कम लागत, सुरक्षित, पूरक चिकित्सा की व्यवहार्यता को दर्शाता है।

स्थैतिक संदर्भ

- संगीत चिकित्सा = व्यक्तिगत चिकित्सीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगीत हस्तक्षेपों का एक नैदानिक और साक्ष्य-आधारित उपयोग।
- के माध्यम से काम करता है: एनेस्थीसिया के तहत भी श्रवण प्रांतस्था गतिविधि सहानुभूति (लड़ाई-या-उड़ान) प्रतिक्रिया में कमी एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन की रिहाई
- गैर-औषधीय दर्द प्रबंधन: ध्यान, श्वास तकनीक, संज्ञानात्मक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, संगीत।
- फेंटेनाइल जैसे ओपिओइड में उच्च निर्भरता क्षमता होती है; भारत भी दुरुपयोग की बढ़ती चिंताओं का सामना कर रहा है।

1. स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए महत्व

- लागत में कमी: कम एनेस्थीसिया + कम ओपिओइड = कम उपचार लागत।
- तेजी से ठीक होने से अस्पताल में रहने की → कम हो जाती है और अत्यधिक बोझ वाले सार्वजनिक अस्पतालों में बिस्तर खाली हो जाते हैं।
- रोगी के अनुभव को बढ़ाता है और पेरीऑपरेटिव चिंता को कम करता है।
- आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और रोगी-केंद्रित देखभाल ढांचे में एकीकृत किया जा सकता है।

2. तकनीकी और नैतिक पहलू

- ऑडियो उपकरणों को शामिल करना, रोगी की निगरानी करना और चिकित्सा कर्मचारियों के साथ संचार सुनिश्चित करना।
- नैतिक आवश्यकता: रोगी को संगीत के बावजूद आवश्यक निर्देश सुनना चाहिए।

3. सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व

- साइड इफेक्ट वाली दवाओं पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।
- एकीकृत चिकित्सा की ओर वैश्विक बदलाव के साथ संरेखित करता है।
- नियमित देखभाल में व्यवहार चिकित्सा को एकीकृत करने के लिए साक्ष्य प्रदान करता है।

4. भारत के लिए निहितार्थ

- संसाधन-बाधित सार्वजनिक अस्पतालों के लिए उपयुक्त कम लागत वाला मॉडल।
- चिकित्सा में न्यूरो-संगीतविज्ञान, चिकित्सा मानविकी और भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।
- ओपिओइड के दुरुपयोग को कम करने और समग्र स्वास्थ्य सेवा में सुधार के भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है।

समाप्ति

दिल्ली परीक्षण से पता चलता है कि संगीत चिकित्सा एनेस्थीसिया के लिए एक प्रभावी, सुरक्षित और किफायती पूरक के रूप में काम कर सकती है, जिससे सर्जरी के दौरान तनाव और नशीली दवाओं के उपयोग को कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती मांगों और सीमित संसाधनों के साथ, इस तरह के गैर-औषधीय, साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों को एकीकृत करने से भारत की चिकित्सा प्रणाली में सुधार हो सकता है, रोगी कल्याण में सुधार हो सकता है और दवा-आधारित प्रक्रियाओं का बोझ कम हो सकता है।

संगीत - भारत की सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित - मुख्यधारा के स्वास्थ्य सेवा उपकरण बनने के लिए तैयार प्रतीत होता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में संगीत चिकित्सा जैसे गैर-औषधीय हस्तक्षेपों के महत्व पर चर्चा करें, हाल ही में दिल्ली में किए गए अध्ययन में एनेस्थीसिया की आवश्यकता में कमी दिखाई गई है। (250 शब्द)

In news : Prelims

73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायतों और नगर पालिकाओं को सशक्त बनाकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम थे। हालांकि, व्यवहार में, स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं और उच्च सरकारों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं।

16वें वित्त आयोग (FC) द्वारा अपनी रिपोर्ट (17 नवंबर, 2025) प्रस्तुत करने के साथ, नए सिरे से उम्मीद है कि यह अंततः स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने के लिए एक स्थिर, पूर्वानुमानित और प्रदर्शन-संवेदनशील राजकोषीय ढांचा प्रदान करेगा।

What can local bodies expect from the 16th FC?

What do the 73rd and 74th constitutional amendments mandate? What have multiple State Finance Commission reports recommended? How have Union Finance Commissions failed to bring about substantial changes, especially with respect to performance-linked grants?

EXPLAINER

V. N. Alok

The story so far:

On November 17, the 16th Finance Commission (FC) submitted its report to the President of India.

What are the expectations?

Main expectations include a percentage share for vertical transfer of resources from the Central revenue pool to the States for the next five years and the formula of its horizontal distribution among States. This is mandated under Article 280 of the Constitution.

What about panchayats, municipalities?

The other expectation is the recommendation to improve the finances of panchayats and municipalities as mandated under Article 280 (3) b and c.

Like many other federations, local governments are the ones rendering essential public services, including drinking water, sanitation, public health, rural roads, maintenance of community assets etc. For this purpose, panchayats and municipalities are mandated to collect certain taxes like property tax, advertisement tax and non-taxes such as market fee, toll etc. However, a huge gap between revenues and expenditure responsibilities can be seen across States and Union Territories (UTs).

As per the 73rd and 74th constitutional amendments, State governments have the power to assign revenue handles and expenditure responsibilities to various rungs of panchayats and levels of municipalities. Due to this reason, there is a wide variation in fiscal powers of panchayats, municipalities across States.

In an ideal scenario, functional responsibilities should be closely linked to the financial powers delegated to local governments. However, there is no separate list for either functional responsibilities or revenue handles that



A major revamp: Collector S. Saravanan taking part in a gram sabha meeting held at Adiyanothu panchayat near Dindigul, Tamil Nadu, on October 11. KARTHIKEYAN G

should be assigned to panchayats and municipalities. While the 11th and 12th Schedules enumerate on 29 broad subjects for panchayats and 18 matters for municipalities respectively, they are merely illustrative and not binding. Moreover, it is the Union and State governments that are expected to design vertical schemes on economic development and social justice, while local governments implement them.

State governments tend to assign responsibilities to local governments without concomitant revenue handles or officials. As a result, panchayats and municipalities bear the financial brunt which not only affects their development but operational efficiency as well.

What is the role of the SFC?

Every five years, States constitute a State Finance Commission (SFC) which can make recommendations to State legislature. The recommended

devolutions by SFC could be, *inter alia*, that panchayats and municipalities should have a share in the revenue pool of the State; be assigned revenue handles; receive both conditional and unconditional grants-in-aid; that local governments be assigned civic functions and functionaries; and various other administrative measures. More than a hundred SFC reports have been submitted across States, but hardly a few have been respected.

In such a situation, the local government must count entirely on fiscal transfers from the Union government. For this purpose, the Constitution mandates the Union Finance Commission (UFC) to suggest measures to augment State finances for local governments.

What did the previous UFCs do?

So far, recommendations of six UFCs have been implemented. However, they weren't able to quantify the resource

requirements of local governments, and made ad hoc arrangements and recommended lump sum grants. The 13th UFC, however, suggested calculating the grant as a percentage share in the union tax divisible pool. The 13th UFC did this consciously after a round of consultations with top legal experts and at the demand of the Union Ministry and several State governments. Neutrality to inflation was the first advantage of the proposal and share of local government in high buoyancy of union tax proceeds was the second major benefit. Sadly, the subsequent UFC took a complete U-turn and recommended lump sum grants. The 15th UFC followed its immediate predecessor in its route of fiscal transfers to local governments. This was not the only discontinuity in the recommendations made by the three successive bodies. The other major anomaly was in the form of conditional grants. In their zeal to reform panchayat and municipal administration, all these UFCs divided the grants into two components – basic and performance-based. While basic grants were unconditional, performance grants were tied to certain conditions identified by these UFCs as reform instruments. However, each UFC ensured to discontinue the line of reform initiated by the previous UFC. To illustrate, the 13th UFC stipulated six conditions for performance grants. None of the conditions could be fulfilled by most States. The 14th UFC refused to acknowledge any merit in the previous reform agenda and recommended fresh conditional performance grants. The conditions put forth by the 15th UFC were again of a different variety.

The 16th UFC, it is expected, must have gone beyond the oft-beaten approach and assessed the resource requirements of 2.7 lakh panchayats and about 5,000 municipalities, which would enable them to act as institutions for economic development and social justice.

V. N. Alok is professor at the Indian Institute of Public Administration.

THE GIST

As per the 73rd and 74th constitutional amendments, State governments have the power to assign revenue handles and expenditure responsibilities to various rungs of panchayats and levels of municipalities.

Every five years, States constitute a State Finance Commission (SFC) which can make recommendations to State legislature.

So far, recommendations of six UFCs have been implemented. However, they weren't able to quantify the resource requirements of local governments, and made ad hoc arrangements and recommended lump sum grants.

सैतिक संदर्भ

1. 73वां और 74वां संविधान संशोधन

- पंचायतों (भाग IX) और नगर पालिकाओं (भाग IX-A) को संवैधानिक दर्जा दिया।
- 11वीं अनुसूची (29 विषय) और 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी गई - लेकिन ये उदाहरणात्मक हैं, बाध्यकारी नहीं हैं।
- राज्य निर्णय लेते हैं:
 - कार्यात्मक जिम्मेदारियां
 - कराधान शक्तियां

◦ स्टाफिंग और प्रशासनिक नियंत्रण

- हर 5 साल में राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) को अनिवार्य किया जाता है।
- केंद्रीय वित्त आयोग (यूएफसी) को स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने का आदेश दिया (अनुच्छेद 280 (3) (बीबी) और (सी))।

2. राज्य वित्त आयोग (एसएफसी)

एसएफसी सिफारिश कर सकते हैं:

- स्थानीय निकायों के लिए राज्य राजस्व का हिस्सा
- करों का असाइनमेंट
- अनुदान (सशर्त/बिना शर्त)
- हस्तांतरण सूत्र
- प्रशासनिक सुधार

समस्या:

100+ SFC रिपोर्टों के बावजूद, अधिकांश राज्य उनकी सिफारिशों की अनदेखी करते हैं।

3. केंद्रीय वित्त आयोग (UFC) और स्थानीय निकाय

- UFC ने 1995 से स्थानीय निकायों के लिए अनुदान लागू किया है।
- 13वां वित्त आयोग - स्थानीय निकायों के लिए विभाज्य पूल के प्रतिशत हिस्से की सिफारिश करने वाला केवल एक।
- 14वें और 15वें वित्त आयोग - एकमुश्त अनुदान पर वापस आ गए, जो उछाल या मुद्रास्फीति से जुड़े नहीं हैं।
- बुनियादी बनाम प्रदर्शन अनुदान:
 - 13वां वित्त आयोग: 6 शर्तें काफी हद तक अधूरी →
 - 14वां वित्त आयोग: नई शर्तें (पिछले सुधार एजेंडे को नजरअंदाज किया गया)
 - 15वां वित्त आयोग: फिर से नई स्थितियां, नीतिगत अस्थिरता पैदा कर रही हैं

करेंट अफेयर्स विश्लेषण

1. 16वें वित्त आयोग से क्या देने की उम्मीद है

- राज्यों को करों का एक ऊर्ध्वाधर हिस्सा (कोर एफसी जनादेश)।
- राज्यों के बीच एक क्षैतिज वितरण सूत्र।
- लेकिन महत्वपूर्ण रूप से:
अनुच्छेद 280 (3) के तहत पंचायत और नगरपालिका वित्त को मजबूत करने के लिए स्पष्ट उपाय।

क्योंकि पूरे भारत में स्थानीय राजस्व और उनकी व्यय जिम्मेदारियों के बीच राजकोषीय अंतर बहुत बड़ा है।

2. स्थानीय निकाय इतने कमजोर क्यों हैं?

- राज्य राजस्व संभाल सौंपे बिना स्थानीय निकायों को कार्य सौंपते हैं।
- स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व शक्तियों की कोई निश्चित सूची नहीं।
- स्थानीय निकायों को धन या कर्मचारियों के मिलान के बिना संघ/राज्य योजनाओं को लागू करना चाहिए।
- यह बनाता है:
 - उच्च बोझ
 - कम स्वायत्तता
 - खराब सेवा वितरण

3. पिछले UFC की विफलता

एक। वास्तविक संसाधन आवश्यकताओं का आकलन करने में विफलता

अधिकांश UFC ने स्थानीय सरकार की जरूरतों को निर्धारित करने के बजाय तदर्थ, एकमुश्त अनुदान का उपयोग किया।
जन्म। प्रदर्शन अनुदान शर्तों में लगातार परिवर्तन

प्रत्येक वित्त आयोग ने पिछले एक के सुधार एजेंडे को खारिज कर दिया -

- 13 वां एफसी: 6 प्रदर्शन की स्थिति
- 14वां वित्त आयोग: सुधारों का नया सेट
- 15वीं एफसी: पूरी तरह से अलग स्थितियां

इससे यह हुआ: नीति विच्छेदन शून्य दीर्घकालिक सुधार राज्य स्थानांतरण शर्तों को पूरा करने में असमर्थ

c. कर उछाल के साथ कोई संबंध नहीं

केवल 13वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल को स्थानीय निकाय अनुदान से बंधा - मुद्रास्फीति के प्रति तटस्थ और उच्च कर वृद्धि से लाभान्वित हुआ। लेकिन बाद में एफसी वास्तविक मूल्य के क्षरण → स्थिर एकमुश्त अनुदान पर वापस आ गए।

4. 16वें वित्त आयोग को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए (विशेषज्ञों के अनुसार)

- वास्तविक व्यय आवश्यकताओं का अनुमान लगाएं:
 - 2.7 लाख पंचायतें
 - 5,000 नगर पालिकाएं
- प्रदान करना:
 - स्थिर सूत्र
 - मुद्रास्फीति-तटस्थ स्थानान्तरण
 - पूर्वानुमानित प्रदर्शन-लिंकड अनुदान

- राज्यों को प्रोत्साहित करें:

- एसएफसी को मजबूत करना
- कर शक्तियां असाइन करें
- स्थानीय संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क को युक्तिसंगत बनाएं

समाप्ति

प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थानीय निकायों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। पिछले वित्त आयोग तदर्थ अनुदान और स्थानांतरण शर्तों के कारण लगातार, पर्याप्त और प्रदर्शन से जुड़ी सहायता प्रदान करने में विफल रहे हैं।

16वें वित्त आयोग के पास अब वास्तविक स्थानीय जरूरतों का आकलन करके और एक स्थिर राजकोषीय ढांचा स्थापित करके इन दीर्घकालिक कमजोरियों को ठीक करने का अवसर है। एक मजबूत डिजाइन पंचायतों और नगर पालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सच्चे संस्थानों में बदल सकता है, जो 73वें और 74वें संशोधनों के इरादों को पूरा कर सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: 13वें वित्त आयोग (FC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसने स्थानीय निकायों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल के प्रतिशत के रूप में अनुदान की सिफारिश की।
2. इसने छह सुधार शर्तों के साथ प्रदर्शन-आधारित अनुदान पेश किया।
3. इसने स्थानीय अनुदानों को मुद्रास्फीति से जोड़ने की प्रथा को बंद कर दिया।

सही उत्तर का चयन कीजिए: (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

Unpacking the global 'happiness' rankings

Why is Finland the happiest country in the world for the eighth year in a row while India languishes at 118? How can Pakistan, which is struggling with political instability and recurring International Monetary Fund (IMF) bailouts score higher than India, the world's fastest-growing major economy? What does this really say about how we define "happiness"?

The World Happiness Report 2025, by the Wellbeing Research Centre at Oxford, again places Finland, Denmark, Iceland and Sweden at the top. India's score is 4.389 of 10, averaging 124 over the years; Pakistan is 109. The contrast seems puzzling against the economic and social realities of both nations.

India, with a \$3.7 trillion GDP, is the world's fifth-largest economy; Pakistan's \$375 billion GDP is barely 10% of that. India's digital economy is booming, and its infrastructure is expanding, whereas Pakistan survives on repeated bailouts. Yet, Pakistan appears "happier"?

Is happiness an economic measure, a perceptual one, or a proxy for something else?

The mirage of metrics

The report relies on the Gallup World Poll's Cantril Ladder, where people rate their lives from 0 to 10, linked with six variables – GDP per capita, social support, life expectancy, freedom, generosity and corruption perception. But perceptions are slippery.

Societies with low expectations often report higher happiness because people adapt to hardship. In vibrant democracies such as India, rising aspirations and constant media scrutiny can lower perceived satisfaction even as well-being improves. When citizens expect better governance or cleaner cities, dissatisfaction reflects higher expectations, not misery.

That paradox explains why the United States has fallen to 24 despite record wealth, while the Nordic nations with high taxes but deep social trust dominate.

The report itself admits that "belief in community kindness" and social trust predict

Souryabrata Mohapatra

is an Assistant Professor of Economics in the School of Liberal Arts, IIT Jodhpur, Rajasthan

Ankita Sharma

is a Full Professor of Psychology in the School of Liberal Arts and Coordinator of Rekhi Happiness Group, IIT Jodhpur, Rajasthan

Suman Dhaka

is an Assistant Professor of Psychology in the School of Liberal Arts, IIT Jodhpur, Rajasthan

Dissatisfaction, for instance, could reflect higher expectations, and not misery

happiness better than income.

India's challenge, then, is not growth but connection. Nearly 19% of young adults globally say they have no one to rely on – up 39% since 2006. With migration and digital life reshaping relationships, Indians too face shrinking real-world networks and expanding virtual ones – prosperity without proximity.

The politics of perception

Critics note that global indices rest on perception-based biases. A 2022 paper by the Economic Advisory Council to the Prime Minister (Sanjeev Sanyal and Aakanksha Arora) showed that indices such as Freedom House and V-Dem depend on small, opaque pools of western "experts". Their subjective views skew results.

A one-party state may appear freer simply because dissent is absent; media-controlled regimes look "stable" because citizens voice fewer complaints. Democracies, by contrast, are penalised for openness. The World Happiness Report risks repeating that error – valuing calm conformity over democratic cacophony. India's low score may reflect self-critical awareness – a maturing democracy unwilling to be complacent.

India's rank has swung between 94th and 144th in a decade. The best phase came in 2022 with post-COVID-19 pandemic recovery and welfare programmes such as Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. The worst was in 2012 amid corruption scandals and slowdown. But happiness rarely tracks fiscal performance. Studies show that social trust, fairness and community matter far more.

In Finland, people believe a lost wallet will be returned – a proxy for institutional trust. In India, governance unevenness erodes that confidence, though local and familial trust remain strong. The COVID-19 lockdown exposed this: millions returned to villages not only for work loss but because community bonds offered the security absent in cities. Such informal trust, ignored by global metrics, sustains resilience.

The report's behavioural framework also carries the WEIRD bias – Western, Educated,

Industrialised, Rich and Democratic. It privileges institutional trust that is typical of individualistic societies and overlooks collective trust networks in countries such as India, where family and community are the real safety nets.

Even so, institutional trust is evolving. Campaigns around mental health, workplace wellbeing and inclusion mark a cultural shift. Programmes such as Tele-MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States) and Mind India place emotional resilience on the policy map. Happiness, once dismissed as a luxury, is now a governance concern.

Aspirations to empathy

To climb the happiness ladder, India must pair economic ambition with empathy infrastructure – investing not only in GDP but also in GNH (Gross National Happiness) through three pathways. First, rebuild social capital. Create community spaces, shared meals and inter-generational ties. The report finds that household size and belief in community kindness significantly raise happiness.

Second, restore institutional trust. Simplify citizen-state interactions. When public services – from ration cards to railway tickets – work transparently, trust follows.

Third, recognise mental health as economic policy. Productivity gains mirror psychological wellbeing. The World Health Organization (WHO) estimates that every \$1 spent on mental health yields \$4 in returns – an investment no economy should ignore. As *The Pursuit of Happiness* reminds us, happiness is not something we possess. It is something we pursue. India's restlessness – its debates, innovations and demands for better lives – may be the clearest sign of wellbeing. Less satisfaction does not mean unhappiness. It signals ambition.

If rank 118 means that Indians still seek cleaner air, fairer governance and fuller lives, perhaps the nation is not unhappy but just unfinished, still chasing a truer idea of happiness.

The views expressed are personal

GS. Paper 2 शासन

UPSC Mains Practice Question : वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की निचली रैंकिंग वास्तविक सामाजिक कल्याण के बजाय धारणा के मुद्दों को दर्शाती है। बढ़ती आकांक्षाओं, संस्थागत विश्वास और सामाजिक पूंजी के आलोक में चर्चा करें। (250 शब्द)

संदर्भ:

वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में एक बार फिर फिनलैंड को लगातार 8वें वर्ष सबसे खुशहाल देश के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि भारत 118वें स्थान पर है। यह विरोधाभास – एक अमीर, तेजी से बढ़ता भारत संकटग्रस्त पाकिस्तान से नीचे है – इस बारे में गहरे सवाल उठाता है कि क्या "खुशी" एक आर्थिक उपाय है, एक समाजशास्त्रीय है, या बस एक धारणा-आधारित निर्माण है

स्थैतिक संदर्भ

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है?

- 2012 से प्रतिवर्ष प्रकाशित।
- केंट्रिल लैडर (0-10 स्केल) का उपयोग करके गैलप वर्ल्ड पोल पर आधारित।
- प्रमुख संकेतक:
 1. प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
 2. सामाजिक समर्थन
 3. स्वस्थ जीवन प्रत्याशा
 4. चुनाव करने की स्वतंत्रता
 5. उदारता
 6. भ्रष्टाचार की धारणा

अजीब पूर्वाग्रह (पश्चिमी, शिक्षित, औद्योगीकृत, अमीर, लोकतांत्रिक)

- सूचकांक मानता है कि पश्चिमी शैली का संस्थागत विश्वास = सार्वभौमिक खुशी मानक।
- भारत जैसे सामूहिक विश्वास समाज को अक्सर कम आंका जाता है।

नॉर्डिक देश हमेशा शीर्ष पर क्यों रहते हैं?

- उच्च संस्थागत विश्वास
- समाज कल्याण
- कम भ्रष्टाचार
- मजबूत सामुदायिक नेटवर्क
- पूर्वानुमानित शासन

वर्तमान संदर्भ

भारत का विरोधाभास: तेज विकास, कम "खुशी" रैंक

- भारत: 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, तेजी से डिजिटल क्षेत्र, तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास।
- फिर भी, स्कोर = 4.389/10, रैंक = 118।
- पाकिस्तान: आर्थिक संकट + आईएमएफ बेलआउट अभी तक 109 पर →।

क्यों? क्योंकि खुशी के स्कोर धारणा को मापते हैं, वास्तविक कल्याण नहीं।

भारत की निचली रैंक के प्रमुख कारण

1. आकांक्षाएं संतुष्टि से भी तेजी से बढ़ रही हैं

- लोकतंत्र उच्च उम्मीदें → अधिक आलोचना → कम रिपोर्ट की गई संतुष्टि उत्पन्न करते हैं।

- लोग बेहतर शासन, स्वच्छ शहरों, निष्पक्षता की अपेक्षा करते हैं - इसलिए असंतोष ≠ नाखुशी; यह महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।
2. सामाजिक विश्वास की कमी
- नॉर्डिक उदाहरण: यदि आप अपना बटुआ छोड़ देते हैं, तो लोगों का मानना है कि यह वापस कर दिया जाएगा।
 - भारत: असमान शासन संस्थागत विश्वास को कम करता है।
3. डिजिटल अलगाव
- वैश्विक वृद्धि: 19% युवा वयस्कों का कहना है कि उनके पास "भरोसा करने के लिए कोई नहीं है"।
 - भारत को वास्तविक जीवन के सिकुड़ते सामाजिक नेटवर्क का भी सामना करना पड़ रहा है।
4. धारणा-आधारित सूचकांक लोकतंत्रों को दंडित करते हैं
- जैसा कि ईएसी-पीएम अध्ययन से पता चलता है, सूचकांक छोटे पश्चिमी विशेषज्ञ पूल पर निर्भर करते हैं।
 - प्रतिबंधित मीडिया वाले देश "स्थिर" दिखाई देते हैं क्योंकि कम शिकायतें रिपोर्ट की जाती हैं।
 - लोकतंत्र आवाज की समस्याओं को कम रैंक → है।

वैश्विक मेट्रिक्स द्वारा नजरअंदाज की गई ताकत

- भारत में मजबूत पारिवारिक और सामुदायिक बंधन हैं, जो विशेष रूप से कोविड-19 प्रवास के दौरान दिखाई देते हैं।
- इन अनौपचारिक ट्रस्ट नेटवर्क को पश्चिमी शैली के सर्वेक्षणों द्वारा कब्जा नहीं किया जाता है।

भारत में सकारात्मक बदलाव

- मानसिक स्वास्थ्य पहल:
 - टेली-मानस
 - कार्यस्थल की भलाई, समावेशन
 - सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य धक्का
- "सकल राष्ट्रीय खुशी" का विचार नीतिगत कर्षण प्राप्त कर रहा है।

भारत को क्या करने की जरूरत है

1. सामाजिक पूंजी का पुनर्निर्माण करें
- सामुदायिक स्थान, साझा कार्यक्रम, अंतर-पीढ़ीगत संबंध।
 - रिपोर्ट से पता चलता है कि घरेलू आकार और सामुदायिक दयालुता खुशी के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई है।
2. संस्थागत विश्वास को मजबूत करें
- नागरिक-राज्य बातचीत को सरल बनाएं।
 - पारदर्शी सार्वजनिक सेवाएं → खुशी → विश्वास करती हैं ।

3. मानसिक स्वास्थ्य को आर्थिक नीति के रूप में मानें

- डब्ल्यूएचओ: मानसिक स्वास्थ्य पर \$ 1 = \$ 4 उत्पादकता लाभ।
- भावनात्मक लचीलापन ढांचा बनाएं।

समाप्ति

भारत का निम्न स्तर राष्ट्रीय नाखुशी का संकेत नहीं देता है; यह बढ़ती आकांक्षाओं और आत्म-आलोचनात्मक जागरूकता वाले समाज को दर्शाता है। कम उम्मीदों के कारण उच्च स्कोर करने वाले अनुरूपतावादी समाजों के विपरीत, भारत का "असंतोष" बेहतर जीवन, स्वच्छ शासन और पूर्ण अधिकारों के लिए इसकी महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित कर सकता है।

यदि रैंक 118 का मतलब है कि भारतीय अधिक निष्पक्षता, अधिक विश्वास, अधिक कल्याण चाहते हैं - तो भारत दुखी नहीं है; यह अधूरा है, अभी भी खुशी के एक गहरे, अधिक वास्तविक विचार का पीछा कर रहा है।